

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्राचार्य,
जी.बी. पन्त इंजीनियरिंग कालेज,
घुडदौड़ी पौड़ी।

शिक्षा अनुभाग-8 (तकनीकी)

देहरादून: दिनांक 26 मार्च, 2007

विषय:- जी.बी. पन्त इंजीनियरिंग कालेज में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु मनोरजन हाल के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-465/2007 दिनांक 13.2.2007 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 में संलग्न पुनर्विनियोग प्रपत्र के अनुसार जी.बी. पन्त इंजी० कालेज घुडदौड़ी में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु मनोरजन हाल के निर्माण हेतु, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम, कालेज इकाई पौड़ी द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष रू० 29.25 लाख (रुपये उनतीस लाख पच्चीस हजार मात्र) के आगणन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- 2- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरे शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी है, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- 3- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन /मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
- 4- एक मुश्त प्राविधान में कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 5- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- 6- कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।
- 7- निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग लाया जाए।

- 8- जी.पी. डब्ल्यू फार्म-9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आंगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।
- 9- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047.XIV-219 (2006) दिनांक 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आंगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
- 10- यह आदेश वित्त विभाग अशासकीय संख्या-1505/वित्त अनुभाग-3/2007 दिनांक 23.03.2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)

उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, पौड़ी।
3. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
4. वित्त अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग।
- ✓ 5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय देहरादून।
7. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, कालेज इकाई पौड़ी।
8. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव।